



जंगल में आग लग जाए तो जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पर आग के बाद समृद्ध जैवविविधता (बायोडायवर्सिटी) वाले नए इकोसिस्टम का विस्तार भी होता है। कैलिफोर्निया के जले हुए जंगलों में बैक कैच वुडपेकर्स (कठफोइवा की एक प्रजाति) की उपस्थिति सर्वव्यापी है। आग लगने के बाद जो विविधतापूर्ण लैण्डस्केप बचता है उसका सबसे ज्यादा फायदा पक्षियों को ही होता है। जले हुए और मृत वृक्षों में छेद करके बीटल्स (कीड़े) घर बनाते हैं और पक्षी उन्हें खाते हैं। यही नहीं, वुडपेकर्स का योगदान भी महत्वपूर्ण है, ये अन्य प्रजातियों के लिए जगह बनाते हैं। पक्षी व छोटे स्तनपायी, वुडपेकर्स द्वारा त्यागी गई प्रजनन साइट का इस्तेमाल करते हैं। तथापि, फायर रिक्वरी ऑपरेशन्स में वुडपेकर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जले हुए जंगल को रिवाइव करने की जल्दबाजी में अधिकारी और फायर मैनेजर्स को यह डेटा एकत्रित करने में बहुत मुश्किल होती है कि, पक्षी कहीं पर हैं। फिर, अधजले पेड़ों को छटने आदि की जो कार्यवाही होती है उससे इन पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है, इनके आवास नष्ट हो जाते हैं। कॉर्नेल लैब ऑफ ऑनिलॉजी एवं कॉर्नेल एटकिन्सन सेंटर फॉर सस्टेनैबिलिटी के पोस्ट डॉक्टर फेलो एण्ड स्टिलमैन ने कहा कि, कई इकोसिस्टम में आग लगने के हालात से जानवरों ने अनुकूलन कर लिया है। स्टिलमैन व उनकी टीम ने एक ऑनलाइन टूल बनाया है जो जले हुए जंगल में बैक बैक वुडपेकर की मौजूदगी के बारे में बताता है। इस टूल की मदद से अधिकारियों को यह पता लगेगा कि किस जगह वुडपेकर्स की संख्या ज्यादा है तथा इस जानकारी के बाद उन क्षेत्रों से जले पेड़ नहीं हटाए जाएंगे। इकोलॉजिकल एप्लीकेशन्स जर्नल में मार्च 2023 में छपे एक शोध, जिसके सहलेखक स्टिलमैन हैं, में पाया गया कि, वयस्क वुडपेकर्स उन वृक्षों पर घर बनाते हैं जो ज्यादा जले हों, और लगभग मर चुके वृक्षों के पास ही वे भीजन ढूँढते हैं। पर, अगर ये सारा समय ज्यादा जले वृक्षों के पास ही बिताते हैं तो उनके बच्चों के जिंदा रहने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए इन्हें कम जले हुए वृक्षों की भी जरूरत होती है। टूल में ये सब नतीजे हैं, जिनसे अधिकारियों को लाभ हो सकता है।

राहुल गांधी क्या ए.आई.सी.सी. के पुनर्गठन में कोई पद लेंगे?

प्रियंका गांधी का क्या होगा? क्या वे "स्टार प्रचारक" की भूमिका से ही संतुष्ट रहेंगी तथा कोई अन्य पद और जिम्मेवारी लेंगी?

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जून। ए.आई.सी.सी. और विभिन्न राज्य इकाइयों में होने वाले फेरबदल को लेकर अटकलें और अनुमान तेज होते जा रहे हैं, साथ ही डिबेटिंग लिस्ट पर प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है- राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी तथा वे ए.आई.सी.सी. में कोई पद लेंगे या नहीं?

प्रियंका गांधी की स्थिति क्या रहेगी? उनकी भूमिका और पद क्या होगा? तीसरा सर्वाधिक चर्चित प्रश्न जिस व्यक्ति को लेकर है, वे हैं ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के दाएं हाथ माने जाते हैं। क्या वे इस पद पर बने रहेंगे या खड़गे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में सफल हो जायेंगे?

रणदीप सिंह सुरजेवाला पदोन्नति पाने तथा वेणुगोपाल के पद पर आने के लिये जबरदस्त लामबंदी कर रहे हैं, किन्तु साफ बात यह है कि राहुल इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पार्टी केरल से रमेश चेत्रियाला, शशि थरूर को समायोजित करना चाहती है तथा वेणुगोपाल तो पहले से ही मौजूद

- अगर राहुल गांधी कोई पद नहीं लेंगे तो उनका ऑफिस कहां होगा?
- प्रियंका गांधी क्या यू.पी. की जिम्मेवारी छोड़ेंगी, क्योंकि स्वयं भी एम.पी. का चुनाव लड़ना चाहती हैं।
- तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ए.आई.सी.सी. के पुनर्गठन में के.सी. वेणु गोपाल के बारे में है? क्या खड़गे उन्हें ए.आई.सी.सी. के संगठन इन्चार्ज के पद से हटा पाएंगे?
- सुरजेवाला, वेणु गोपाल का पद लेने के लिये लालायित हैं।
- केरल के संदर्भ में खड़गे का "कास्ट" समीकरण बिठाना भी मुश्किल है। तीन उम्मीदवार हैं, वेणु गोपाल, रमेश चेत्रियाला व शशि थरूर, तीनों "नायर" हैं, अतः किसको बनायें, किसको नहीं बनायें कठिन सवाल है।
- पर, लोग उम्मीद करते हैं कि, खड़गे विशाल हृदयता दिखायेंगे तथा थरूर, जो उनके खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे, को सी.डब्ल्यू.सी. का सदस्य बनायेंगे।
- अभी काफी अनिश्चितताएं हैं, राहुल गांधी के आने के बाद, कुछ स्थिति साफ होगी?

हैं। ये तीनों ही "नैयर" जाति से हैं तथा इसलिये जातिगत समीकरणों को संतुलित करने में मुश्किल आ रही है। खड़गे के लिये यह दिखाना जरूरी है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, इसलिये उनके लिये शशि थरूर को सी.डब्ल्यू.सी. में समायोजित करना जरूरी है लेकिन जातिगत समीकरण बहुत बड़ी समस्या सिद्ध हो रहे हैं। राहुल गांधी ने स्वयं महात्मा गांधी के स्तर तक ऊपर उठा लिया है तथा वे

पदों से परे एवं ऊपर हो गये हैं। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि वे सत्ता के पीछे की सत्ता होंगे। लेकिन अब राहुल 10 जनपथ पहुँच गये तथा अपनी माँ के साथ रहते हैं। सोनिया, प्रियंका तथा राहुल तीनों के दफ्तर भी 10 जनपथ में ही हैं। सुत्रों का कहना है कि राहुल अब किसी दफ्तर की तलाश में हैं क्योंकि उनके पास ए.आई.सी.सी. का कोई पद नहीं होने के कारण, उन्हें पार्टी मुख्यालय

में कोई दफ्तर नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी अब स्टार प्रचारक हैं। लेकिन वे चुनाव भी लड़ना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में, क्या वे उत्तर प्रदेश का प्रभार छोड़ देंगी तथा संगठन में कोई बड़ी भूमिका लेंगी, या फिर वे सांसद बनने पर ध्यान केन्द्रित करेंगी। प्रश्न बहुत सारे हैं किन्तु एक साफ और सटीक उत्तर किसी प्रश्न का नहीं है। पत्रकार अटकलें लगाने में लगे हुये हैं लेकिन अभी तक कोई (शेष पृष्ठ 5 पर)

एक साल में चीन में शादियों की संख्या में 10 प्रतिशत कमी हुई!

क्यों युवाओं में शादी की परम्परा अपनाने में इतनी अरुचि बढ़ रही है?

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जून। चीन नई सुपर पावर बनने की दिशा में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहा है लेकिन देश के भीतर यह युवा पीढ़ी के साथ गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, जो कि पारम्परिक सामाजिक नियमों से मुंह फेर

- कोविड के दौरान, चीन की सरकार ने बहुत प्रतिबंध लगाये नागरिकों पर। कई दर्दनाक घटनाएँ साक्षी हैं, नागरिक तथा उनकी मानसिक स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ता है, उनके मन में एक सवाल क्रांति रहा है कि, सरकार इतनी आसानी से नागरिकों की स्वतंत्रता नष्ट कर सकती है, तो ऐसी मजबूरी की जिन्दगी अपने बच्चों को देना कहां तक ठीक है?
- दूसरा, बड़ा कारण है, युवतियाँ अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ने से युवतियों को आकर्षक अवसर मिल रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिये। वे इस समृद्धि की उड़ान में परिवार की जिम्मेदारियों का "एक्स्ट्रा बैगेज" नहीं चाहती।

2022 में 6.83 लाख जोड़ों ने ही शादी की जो कि इसके पूर्व वर्ष की संख्या 7.63 लाख से काफी कम है। इसके अलावा शादी की औसत आयु भी बढ़ रही है। एक वर्ष में शादी के आँकड़ों में 10 प्रतिशत की कमी चिंता का विषय है और इसके अवश्य ही गहरे अंतर्निहित कारण हैं।

कुछ लोग इसके लिए कोविड काल में आम आदमी के ट्रामा को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उस समय राज्य सरकार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह खत्म कर दिया था लोगों का घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। एक उदाहरण तो बेहद दर्दनाक है, जब तक ऊँची इमारत में आग लगने से वहां रहे लोग जलकर मर गए, क्योंकि कोविड प्रतिबंधों की वजह से फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने नहीं आ सके थे। इस घटना ने सामाजिक संवेदनशीलता पर ऐसा दाग लगाया जो (शेष पृष्ठ 5 पर)

"कैसलेशन रिपोर्ट" से बृज भूषण को राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जून। दिल्ली पुलिस ने पोक्सो केस की गहन जांच पूरी कर लेने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पृष्ठों की कैसलेशन रिपोर्ट गुरुवार को पेश कर दी। पुलिस ने कहा कि उसके द्वारा की गई जांच नाबालिग

- दिल्ली पुलिस ने रैसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो केस में दर्ज रिपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की है।

लड़की तथा उसके पिता के बयानों पर आधारित है।

खेल मंत्रालय ने जनवरी में एक आंतरिक कमेटी गठित कर दी थी। इस कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसे महिला पहलवानों ने खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के (शेष पृष्ठ 5 पर)

यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दों को भी चर्चा में क्यों लाया गया है?

कांग्रेस का कहना है, यह चर्चा पुनः जागृत करना दर्शाता है कि, मोदी सरकार हताश है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जून। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि भारत के विधि आयोग द्वारा "समान नागरिक संहिता" (यूनिफॉर्म सिविल कोड) पर जनता तथा धार्मिक संगठनों के विचार आमंत्रित करने की कोशिश दर्शा रही है कि, नरेन्द्र मोदी सरकार धुवीकरण तथा "स्पष्ट दिखाई दे रही असफलताओं" से लोगों का ध्यान हटाने के अपने एजेंडा को "विधि सम्मत औचित्य" देने के लिए व्यग्र है।

मुख्य विपक्षी दल ने कहा है कि 22वें विधि आयोग के बयान ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि, ऐसा कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गये निर्देशन (रेफरेंस) पर किया जा रहा है। कांग्रेस के कम्यूनिक्शन प्रमुख जयराम रमेश ने एक बयान में कहा

- कांग्रेस के अनुसार हताश होकर भाजपा सरकार पुनः साम्प्रदायिक धुवीकरण का प्रयास कर रही है, जिससे सरकार की कमियों व खामियों पर ज्यादा ध्यान नहीं जाये।

"विचित्र बात है कि विधि आयोग एक नया रेफरेंस मांग रहा है, जबकि अपनी प्रैस विज्ञप्ति में इसने यह स्वीकार किया है कि इसके पूर्ववर्ती 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में इस विषय पर एक कन्सल्टेशन पेपर प्रकाशित किया था। इस बात का कोई कारण नहीं दिया गया है कि यह विषय फिर से क्यों उठाया जा रहा है, सिवाय इसके कि, इसकी प्रासंगिकता के कुछ अस्पष्ट संदर्भ, इस विषय के महत्व तथा विभिन्न अदालतों के हवाले मात्र दिये गये हैं।" रमेश ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इसका असली कारण यह है कि 21वें

विधि आयोग ने, इस विषय की विस्तृत एवं व्यापक समीक्षा करने के बाद, कहा था कि, "इस स्थिति (स्टेज) में" समान नागरिक संहिता लाना "न तो आवश्यक है और न वांछनीय।" रमेश ने कहा, "यह नई कोशिश मोदी सरकार के धुवीकरण एवं इसकी प्रगति दिखाने दे रही असफलताओं से ध्यान हटाने के इसके सतत एजेंडा के वैध औचित्य के लिये सरकार की हताशा का प्रतिनिधित्व कर रही है।" तथ्य यह है कि 21वें विधि आयोग, जिसकी नियुक्ति मोदी सरकार (शेष पृष्ठ 5 पर)

गुजरात भाजपा प्रमुख को लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जून। गुजरात भाजपा के प्रमुख सी.आर. पाटिल, जो लगातार

- सुत्रों के अनुसार, गुजरात भाजपा प्रमुख सी.आर. पाटिल को आम चुनावों में यू.पी., राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा जैसे राज्यों की जिम्मेवारी दी जा सकती है। बताया जाता है कि, प्र.मंत्री मोदी पाटिल के काम से बेहद खुश हैं।

तीन बार नवसारी से सांसद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा (शेष पृष्ठ 5 पर)

घबराइये नहीं, हवाई यात्रा के दौरान अनियंत्रित आचरण की घटनाएं पूरे विश्व में बढ़ रही हैं, केवल भारत में नहीं

मास्क लगाने की अनिवार्यता हटने के बाद, एक बार तो ऐसी घटनाओं में कुछ समय के लिये कमी आयी थी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जून। भारत में हवाई यात्रियों को उड़ड़ता की घटनाओं के हालिया वृद्धि का रूझान पूरे विश्व में देखा गया है। यह जानकारी मिली है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.) द्वारा एकत्रित डेटा से। वर्ष 2021 में प्रति एक हजार उड़ड़नों में यह दर 1.2 थी अर्थात् दर 835 उड़ड़नों में एक घटना हुई। यह दर वर्ष 2022 में बढ़कर 1.76 हो गई अर्थात् हर 568 उड़ड़ान पर एक घटना। चालक दल के निर्देश नहीं मानना सबसे आम उड़ड़ता है। वर्ष 2021 में प्रति 1000 उड़ड़ान में यह रेट 0.224 प्रतिशत थी जो 2022 में बढ़कर 0.307 प्रतिशत हो गई। गाली-गलौच व धक्का-मुक्की की घटनाएं भी 2022 में बढ़ी हैं। विमानों, खराब व्यवहार की समस्या से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी निरोधक घटनाओं की बेहतर रोकथाम व प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। एयर लाइन्स एवं सरकारें इन घटनाओं में वृद्धि व बदतमीजी को गंभीरता से लेकर चिंतित है। इन घटनाओं में चालक दल और अन्य यात्रियों के साथ हिंसा, उत्पीड़न, गाली-गलौच, धूम्रपान, सुरक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्देशों का पालन नहीं करना व अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार। यद्यपि इस तरह का व्यवहार कुछ

- पर, फिर संख्या काफी तीव्र गति से बढ़ी। वर्ष 2022 के अंत तक वर्ष 2021 की तुलना में इन घटनाओं में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- एयर लाइन्स विशेषज्ञों का मानना है कि, घटनाओं का एक बड़ा कारण है, पलाइंट पकड़ने से पहले एयरपोर्ट के बार रेस्टोरेंट आदि में मदिरा का भारी सेवन या फिर हवाई जहाज में बैठने के बाद, यात्रियों द्वारा प्राइवेट बोटल से शराब पीना।
- विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि, अनियंत्रित आचरण का कितना भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस बात का खूब प्रचार हो, तो शायद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति काफी कम हो सकती है।

पैदा कर सकते हैं, अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरों में डाल सकते हैं, उड़ड़ान संचालन में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। महामारी के बाद इस तरह के व्यवहार में हुई वृद्धि को देखकर आई.ए.टी.ए. ने ज्यादा देशों से कहा है कि ऐसे यात्रियों पर मौंट्रियल प्रोटोकॉल 2014 (एम.पी. 14) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष 2022 में घटनाओं के वर्गीकरण में सबसे आम थी, बात नहीं मानना, गाली-गलौच करना, नशा करना आदि, मार पीट की घटनाएं कम हैं, पर इनमें चिंताजनक वृद्धि हो रही है। वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में इन

घटनाओं में 61 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आई.ए.टी.ए. के डिप्टी डायरेक्टर कोनराड क्लिफर्ड ने कहा कि यात्रियों के उद्ग्रहण के दौरान शांत व सुरक्षित अनुभव का अधिकार है। इसके लिए यात्रियों का चालक दल के निर्देश मानने चाहिए। हमारे पेशेवर कर्मचारी उद्ग्रहण यात्रियों से निपटने में दक्ष होते हैं, पर यह बात स्वीकार्य नहीं है कि नियम सभी की सुरक्षा के लिए पर कुछ लोग लगातार इनका उल्लंघन करते हैं और नियम नहीं मानने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हवाई यात्रा में वृद्धि के साथ यह (शेष पृष्ठ 5 पर)

'हिंसा ग्रस्त मणिपुर सेना के सुपुर्द किया जाए'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 जून। ट्राइबल फोरम ने गुरुवार को एक नई इन्टरलोक्यूटरी अपील (आई.ए.) लगाकर, सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध

- मणिपुर के एक ट्राइबल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है और आरोप लगाया है कि, केन्द्र सरकार व मुख्यमंत्री कुकी आदिवासियों को खत्म करने के साम्प्रदायिक एजेंडा पर काम कर रहे हैं।

किया कि वह भारतीय सेना को निर्देश दे कि सेना दंगा पीड़ित मणिपुर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लो। फोरम ने कहा कि केन्द्र सरकार एवं मुख्यमंत्री के आश्वासन तो निरर्थक हैं क्योंकि ये दोनों (शेष पृष्ठ 5 पर)